

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : अपील/अशोकनगर/भूरा./2018/4331 - विरुद्ध - आदेश  
दिनांक 25-6-2018 - पारित द्वारा - आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर -  
प्रकरण क्रमांक 459/17-18 अपील

- 1- श्रीमती सिरिया वाई पत्नि स्व. अमोल
  - 2- रंजीत 3- अनिल पुत्रगण स्व०अमोल
  - 4- सुश्री दीपा पुत्री स्व० अमोल
- सभी ग्राम कोलुआ तहसील अशोकनगर  
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर अशोकनगर

—अपीलांटस

—रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांटस के अभिभाषक श्री जी०पी०नायक)  
(रिस्पा० के पैनल लायर श्री मुकेश शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 3-4-2019 को पारित)

यह अपील आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक  
459/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-6-2018 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व  
संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारंश यह है कि अपीलांटस ने म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा  
165 के अंतर्गत कलेक्टर अशोकनगर को आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उनके नाम ग्राम  
कोलुआ में सर्वे क्रमांक 109/2/2 रकबा 0.500 हैक्टर भूमि विरासत में प्राप्त भूमि है जिसे वह  
विक्रय करना चाहते हैं, विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर अशोकनगर ने अपीलांटस  
के आवेदन की जांच नायब तहसीलदार अशोकनगर से कराकर प्र०क्र० 7 अ 21/2016-17 में  
आदेश दिनांक 30-1-2017 पारित किया तथा अपीलांटस का भूमि विक्रय आवेदन निरस्त कर  
दिया। कलेक्टर अशोकनगर के आदेश के विरुद्ध आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष  
अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 459/17-18  
अपील में पारित आदेश दिनांक 25-6-2018 से अपील निरस्त कर दी। आयुक्त, ग्वालियर

संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांटस के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अपीलांटस ने कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष उनके नाम की ग्राम कोलुआ स्थित सर्वे क्रमांक 109/2/2 रकबा 0.500 हैक्टर भूमि के विक्रय की अनुमति का आवेदन दिया था कलेक्टर अशोकनगर ने आवेदन के तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार अशोकनगर से कराई है तहसीलदार अशोकनगर ने सभी पक्षकारों को बुलाकर कथन अंकित किये है परन्तु वाद में वह क्या कर रहे हैं कोई सूचना नहीं दी और अपीलांटस से कोई रिकार्ड आदि मांगा, जबकि अपीलांटस ने खसरा एवं भू अभिलेख ऋण पुस्तिका मूल रूप में तहसीलदार को दे दी थी उन अभिलेखों पर विचार नहीं किया गया है। अपीलांटस उक्त भूमि से लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि भूमि मात्र सवा दो बीघा है एवं पथरीली है जिसके कारण उन्हें अशोकनगर जाकर मजदूरी करना पड़ती है यदि असिंचित एवं पथरीली भूमि में मेहनत करके फसल बो देते हैं फसल उगती तक नहीं है जिसके कारण भूमि अलाभकारी है एवं इस भूमि पर संपूर्ण परिवार का गुजारा नहीं होता है। अपीलांटस को भूमि विरासत में स्वर्गीय अमोल से प्राप्त हुई है। चालू रेट से अधिक दर पर विक्रय मूल्य मिल रहा है एवं इस भूमि को विक्रय करके अपीलांटस नजदीक के गाँव में कृषि योग्य जमीन लेना चाहते हैं इस पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने अपील स्वीकार कर विक्रय अनुमति दिये जाने की मांग रखी।

म०प्र०शासन के पैनल लायर ने व्यक्त किया कि अपीलांट के पास केवल ग्राम कोलुआ स्थित सर्वे क्रमांक 109/2/2 रकबा 0.500 हैक्टर भूमि भूमि है यदि उसे विक्रय की अनुमति दी गई और भूमि विक्रय गई, तब वह भूमिहीन हो जावेगें एवं परिवार की आजीविका पर विपरीत असर पड़ेगा एवं भूमिहीन बनकर फिर से पट्टा लेने की लायन में खडे हो जावेगे। कलेक्टर अशोकनगर ने शोच-विचार करके आदेश पारित किया है जिसे यथावत् रखा जावे।

5/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर अशोकनगर ने अपीलांटस के विक्रय अनुमति आवेदन के तथ्यों की नायव तहसीलदार अशोकनगर से कराई है जिन्होंने अपीलांटस को बुलाकर कथन

भी लिये है कि अपीलांट सिरियावाई ने कथनों में बताया है कि भूमि अनउपजाउ है जिसमें काफी मेहनत करने के वाद उक्त भूमि में पैदावार कम होती है जिससे मेरे परिवार का भरणपोषण नहीं हो पाता है इसलिये भूमि विक्रय करना चाहती है। अपीलांट रंजीत ने, सुश्री दीपा ने भी इसी आशय के कथन दिये हैं। कलेक्टर न्यायालय के प्र०क० 7 अ 21/2016-17 में भू अभिलेख ऋण पुस्तिका मूल रूप में संलग्न है जिसमें इस प्रकार की प्रविष्टि है :-

सिरिया वाई वेवा अमोला  
रणजीत, अनिल पुत्रगण अमोला  
दीपा पुत्री अमोला  
जाति चमार नि. ग्राम  
शा.बं.अहस्ता. भूमिस्वामी हिस्सा बराबर

अपीलांट्स के अभिभाषक के अनुसार कभी शासन से स्व.अमोल को पटटा हुआ होगा, किन्तु अपीलांट्स को भूमि स्व.अमोला से विरासत में प्राप्त है। अपीलांट्स ने यह भी बताया है कि केवल दो सवा दो बीघा जमीन है जिसमें परिवार का पेट पालना संभव नहीं है। इसीसे स्पष्ट है कि भूमि अपीलांट के लिये लाभकारी नहीं है जिसके कारण वह उनके स्वामित्व की भूमि अनुसूचित जाति के होने के कारण विक्रय की अनुमति मांग रहे हैं। विचार योग्य है कि क्या अपीलांट्स को स्व. अमोल से विरासत में प्राप्त उनके स्वत्व की भूमि को विक्रय की अनुमति दिये जाने में बैधानिक अड़चन है ?

1. दयाशंकर विरुद्ध हरेराम तथा एक अन्य 2011 रा०नि० 426 का न्याय दृष्टांत है कि -

भू राजस्व संहिता 1959 (म०प्र०) - धारा 165-(7-ख)- पटटाधारक - 10 वर्ष पश्चात् भूमिस्वामी अधिकार प्रोद्भूत - ऐसी भूमि के अंतरण के लिये कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

2. फुल्ला विरुद्ध नरेन्द्र सिंह तथा अन्य 2012 रा. नि. 256 उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये- बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबंध आकर्षित नहीं होते। भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है

ग्राम कोलुआ स्थित सर्वे क्रमांक 109/2/2 रकबा 0.500 हैक्टर भूमि अपीलांट्स को विरासत

में नामान्तरण से प्राप्त भूमि है जिसके विक्रय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है जिसके कारण कलेक्टर अशोकनगर द्वारा एकपक्षीय पारित 30-1-2017 एवं आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-6-2018 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 459/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-6-2018 एवं कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्र०क० 7 अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-1-2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं अपीलांटस को उनके स्वामित्व की कोलुआ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 109/2/2 रकबा 0.500 हैक्टर के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भूमि का विक्रय पत्र संपादित करते समय उप पंजीयक विक्रय दिनांक को प्रचलित गाईड लायन के मान से भूमि की कीमत आदान-प्रदान कराने की संतुष्टि उपरांत विक्रय पत्र संपादित करेंगे। यह आदेश तीन माह तक प्रभावशील रहेगा।

(एस०एस०अली)  
सदस्य

राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर